रेल बजट 2016-17 की मुख्य बातें

बजट की विषय-वस्तु

- **चुनौतियां से निपटना: भारतीय रेल का- पुनर्गठन, पुनर्निर्माण पुनरूद्धार: "चलो, मिलकर कुछ नया करें"।**
- कार्यनीति के तीन स्तंभ अर्थात् **नव अर्जन, नव मानक, नव संरचना।**

वित्तीय निष्पादन

- **2015-16-** 8,720 करोड़ रु. की बचत होने से राजस्व की अधिकांश कमी को पूरा कर लिया जाएगा, संभावित परिचालन अनुपात 90%.
- 2016-17- परिचालन अनुपात का निर्धारित लक्ष्य 92%, 7वें वेतन आयोग का तात्कालिक प्रभाव शामिल करने के बाद साधारण संचालन व्यय को 11.6% तक सीमित रखना, डीज़ल और बिजली खपत में योजनाबद्ध कटौती, 1,84,820 करोड़ रु. के राजस्व सृजन का निर्धारित लक्ष्य।

निवेश और संसाधन

- कार्यात्मक स्तर पर शक्तियों के प्रत्योजन सहित प्रक्रिया संबंधी बाधाएं दूर करने की प्रक्रिया; 2009-14 की अवधि में 48,100 करोड़ रु. का औसत पूंजीगत व्यय और 8% प्रतिवर्ष की औसत वृद्धि।
- 2015-16 में निवेश पिछले 5 वर्ष के औसत से लगभग दुगुना हो जाएगा।
- 2016-17 में पूंजीगत योजना के लिए 1.21 लाख करोड़ रु. रखे गए हैं; पीपीपी के लिए नवीन संरचनाएं आदि विकसित करके, राज्यों के साथ संयुक्त उद्यम, आदि के जरिए कार्यान्वयन।

विज़न

2020 तक आम आदमी की लंबे समय से चली आ रही आशा को पूरा करना अर्थात गाड़ियों में आरक्षित एकोमोडेशन मांग पर उपलब्ध होना, मालगाड़ियॉं समय-सारणी के अनुसार चलना, संरक्षा रिकॉर्ड में सुधार लाने के लिए अत्याधुनिक टैक्नॉलोजी, बिना चौकीदार वाले सभी समपारों को समाप्त करना, उन्नत समय-पालन, माल गाड़ियों की उच्चतर औसत गति, सेमी हाई स्पीड ट्रेनें जो स्वर्णिम चतुर्भुज पर चलें, मानव अपशिष्ट का जीरो डायरेक्ट डिस्चार्ज।

2015-16 की उपलब्धियां

- 2015-16 की 139 बजट उद्घोषणाओं पर कार्रवाई शुरू की गई।

परियोजना निष्पादन

- 2015-16- जीवन बीमा निगम के जरिए सुनिश्चित वित्तपोषण, 2500 किमी बड़ी आमान लाइनों को चालू करना; 1600 किमी का विद्युतीकरण चालू करना; 2016-17 में- 2800 किमी रेलपथ को चालू करने का लक्ष्य निर्धारण; बड़ी आमान लाइनों पर पिछले 6 वर्षों में लगभग 4.3 किमी प्रति दिन की औसत की तुलना में 7 किमी प्रति दिन की गति से चालू करना। यह 2017-18 में लगभग 13 किमी प्रति दिन और 2018-19 में 19 किमी प्रतिदिन तक बढ़ जाएगा। 2017-18 में लगभग 9 करोड़ श्रम दिवस के रोजगार सृजन; 2016-17 में रेलवे विद्युतीकरण के लिए परिव्यय लगभग 50% तक बढ़ाया गया है। इसे 2000 किमी तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है।

समर्पित माल गलियारा

- 31 मार्च 2016 तक सिविल इंजीनियरी निर्माण कार्यों के लिए लगभग सभी ठेके दिए जाने है। पिछले 6 वर्षों में दिए गए 13,000 करोड़ रु. के ठेकों की तुलना में नवंबर 2014 से 24,000 करोड़ रु. के ठेके आबंटित किए गए। सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित नवीन वित्तपोषण के जरिए उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम और पूर्व तट माल गलियारों को शुरू करने का प्रस्ताव।

पोर्ट कनेक्टिविटी

- टूना पोर्ट चालू कर दिया गया है और जयगढ़, दीघी, रेवास और पारादीप के पोर्ट के लिए रेल संपर्क व्यवस्था की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नारगोल और हाजिरा पोर्ट के लिए रेल कनेक्टिविटी का क्रियान्वयन।

पूर्वोत्तर

- असम में बड़ी लाइन पर लमडिंग-सिलचर खंड खोल दिया गया है और इस प्रकार बराक घाटी को शेष देश के साथ जोड़ दिया गया है; अगरतला भी बड़ी लाइन नेटवर्क पर आ गया है। कटखल-भैराबी और अरुणाचल-जीरीबाम की आमान परिवर्तन परियोजनाएं जल्दी ही खोल दिए जाने पर मिजोरम और मणिपुर राज्य भी देश के बड़ी लाइन मानचित्र पर आ जाएंगे।

जम्मू एवं कश्मीर

- उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना का कटरा-बनिहाल खंड का कार्य संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रहा है; कुल 95 किलोमीटर में से, 35 किलोमीटर सुरंग का कार्य पूरा हो गया है; जालंधर-जम्मू लाइन में भीड़-भाड़ कम करने का कार्य पूरी तेजी से चल रहा है और मार्च 2016 तक दो पुलों का दोहरीकरण का कार्य पूरा कर उन्हें चालू कर दिया जाएगा, जबकि अन्य दो पुलों को 2016-17 तक पूरा कर लिया जाएगा।

मेक इन इंडिया: दो लोको फैक्टरियों के लिए बिड को अंतिम रूप दे दिया गया है। ट्रेन सैट की मौजूदा खरीद को 30% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

निम्नलिखित के जरिए भावी क्षमता निर्माण:

- **पारदर्शिता-** 2015-16 में ऑनलाइन भर्ती शुरू की गई, अब सभी पदों के लिए इस प्रक्रिया को अपनाना। सोशल मीडिया को पारदर्शिता लाने में उपकरण के रूप में प्रयोग करना। निर्माण कार्यों की खरीद सहित सभी प्रकार की खरीद ई-प्लेटफार्म पर करना। निविदा इलेक्ट्रॉनिकली आबंटित करने की प्रक्रिया का परीक्षण सफल होने पर 2016-17 में अखिल भारतीय आधार पर शुरू करना।
- **गवर्नेंस:** शक्तियों के प्रत्यायोजन से परियोजना स्वीकृति करने का समय घटकर 6-8 माह तक आ गया है, जिसमें पहले 2 वर्ष लगते थे। महाप्रबंधकों और मंडल रेल प्रबंधकों के निष्पादन का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना, कुछ ज़ोनों के साथ हस्ताक्षरित कार्य निष्पादन से संबंधित समझौता ज्ञापन को सभी ज़ोनों पर अपनाना।
- **आंतरिक ऑडिट उपाय:** कमियों का पता लगाने और वेस्टेज रोकने के लिए कुछ क्षेत्रों में रेल परिचालन की जांच का कार्य विशेषज्ञता टीमों को सौंपना। 31 मार्च 2016 तक प्रत्येक ज़ोन 2 रिपोर्ट तैयार करेगा।
- **साझेदारी-** राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन, 17 ने सहमति प्रदान कर दी है और राज्य सरकारों के साथ 6 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बजट दस्तावेजों में 44 नई साझेदारियों के कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें लगभग 5,300 किमी कवर होगा और जो 92,714 करोड़ रु. मूल्य की हैं।

ग्राहक इंटरफेस

- सोशल मीडिया और समर्पित आईवीआरएस सिस्टम के जरिए संवाद और फीडबैक।
- यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए 65,000 अतिरिक्त शायिकाएं बनाना, 2,500 वाटर वेंडिंग मशीनें लगाना, आधुनिक साज-सज्जा के सवारी डिब्बों वाली 'महामना एक्सप्रेस' चलाना, गाड़ियों में 17,000 जैव-शौचालय की व्यवस्था करना; विश्व का पहला बायो-वैक्यूम टॉयलेट विकसित किया गया है।
- समयपालन में सुधार- गाजियाबाद से मुगलसराय खंड के लिए परिचालन ऑडिट की व्यवस्था करना।

- टिकटिंग- 1,780 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें लगाना; यूटीएस एवं पीआरएस टिकटों की कैशलेस खरीद के लिए मोबाइल एप और गो इंडिया स्मार्ट कार्ड, ई-टिकटिंग सिस्टम की क्षमता को 2000 टिकट प्रति मिनट से बढ़ाकर 7,200 टिकट प्रति मिनट करना और एक ही समय पर 1,20,000 उपयोगकर्ता इसका उपयोग कर सकते हैं जबकि पहले केवल 40,000 ही कर सकते थे।
- सामाजिक पहल: ऑनलाइन टिकट बुक करते समय रियायत पाने के लिए एकबारगी पंजीकरण, दिव्यांगों के लिए व्हील चेयरों की ऑनलाइन बुकिंग और ब्रेल इनेबल्ड नए सवारी डिब्बों का प्रावधान करना; वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए निचली बर्थों का कोटा बढ़ाना; महिलाओं के लिए सवारी डिब्बों में मिडल बे को आरक्षित करना।
- 100 स्टेशनों पर वाई-फाई सेवा शुरू की गई, यह सेवा अन्य 400 स्टेशनों पर शुरू की जाएगी।
- स्टेशन पुनर्विकसित करना- हबीबगंज, भोपाल के लिए वित्तीय बिड प्राप्त हो गई है, स्टेशनों पर पीपीपी के अंतर्गत इसे शुरू करने के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन।
- हेल्पलाइन व सीसीटीवी के जरिए सुरक्षा।
- संरक्षा - चौकीदार वाले 350 समपार बंद करना, बिना चौकीदार वाले 1,000 समपार समाप्त करना, मौजूदा वर्ष में 820 आरओबी/आरयूबी का कार्य पूरा किया गया और 1,350 पर कार्य चल रहा है।

अन्य प्रमुख उपलब्धियां

- ऊर्जा: आगामी वित्त वर्ष में ही अर्थात निर्धारित समय से एक वर्ष पहले 3,000 करोड़ रु. की वार्षिक बचत प्राप्त कर ली जाएगी। यह बचत डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी के रूप में भारतीय रेल की स्थिति का उपयोग कर प्रतिस्पर्धी दरों पर सीधे बिजली खरीदने के कारण होगी।
- रेल विश्वविद्यालय: प्रारंभ में वड़ोदरा स्थित भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी की पहचान की गई है।
- डिजिटल इंडिया: ट्रैक प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) एप्लीकेशन शुरू की गई है, इन्वेंटरी प्रबंधन मॉडयूल की इन्वेंटरी में 27,000 एमटी की कमी आई है, जिससे 64 करोड़ रु. की बचत हुई है और 53 करोड़ रु. मूल्य के समतुल्य 22,000 एमटी स्क्रैप चिह्नित किया गया है।

<u>आगे का मार्ग</u>

यात्रा की गुणवत्ता में सुधार:

अनारक्षित यात्रियों के लिए-

- **अंत्योदय एक्सप्रेस** अनारक्षित, सुपरफास्ट सेवा
- **दीन दयालु सवारी डिब्बे-** पेयजल और बड़ी संख्या में मोबाइल चार्जिंग के पांइटों वाले अनारक्षित सवारी डिब्बे

आरक्षित यात्रियों के लिए

- **हमसफ़र**- पूर्णत: वातानुकूलित 3एसी सेवा जिसमें भोजन के विकल्प की सेवा मौजूद हो
- **तेजस-** तेजस भारत में रेलगाड़ी यात्रा के भविष्य को दिखाएगी। 130 किलोमीटर प्रति घंटा और उससे अधिक गति पर चालित, ये जवाबदेही और उन्नत ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए एक सेवा प्रदाता के माध्यम से ऑनबोर्ड सेवाएं पेश करेगी जैसे मनोरंजन, स्थानीय भोजन, वाई-फाई आदि।
- टैरिफ और नॉन-टैरिफ उपायों के जरिए लागत की वसूली सुनिश्चित करने के लिए **हमसफ़र और तेजस**
- **उदय-** सबसे व्यस्त मार्गों पर रात्रिकालीन डबल डेकर, **उत्कृष्ट डबल** डेकर एयर कंडीशन्ड **यात्री** एक्सप्रेस जो वहन क्षमता को लगभग 40% बढ़ाने की संभावना हैं।

टिकटिंग: हैंड हैल्ड टर्मिनलों के जरिए टिकटों की बिक्री; विदेशी डेबिट/क्रेडिट कार्डों से ई-टिकटिंग सुविधा; पायलट आधार पर बार कोड वाली टिकटें, स्कैनर और एक्सेस कंट्रोल शुरू करेंगे। **विकल्प** योजना का विस्तार किया जाएगा ताकि प्रतीक्षा सूची के यात्री विनिर्दिष्ट गाड़ियों में एकोमोडेट किए जाने के लिए अपनी इच्छा दर्ज करा सकें। पत्रकारों के लिए रियायती पासों पर टिकटों की ई-टिकटों की सुविधा उपलब्ध; हेल्पलाइन 139 पर यात्रियों को पंजीकृत फोन नंबर पर भेजे गए 'वन टाइम पासवर्ड' का उपयोग करते हुए टिकट रद्द कराने की सुविधा, **तत्काल** काउंटरों को उत्तरोतर ढंग से सीसीटीवी के दायरे में लाना और पीआरएस वेबसाइट का आवधिक ऑडिट।

स्वच्छता- एसएमएस के जरिए **'क्लीन माई कोच'** सेवा, नियमित अंतराल पर तीसरी पार्टी ऑडिट और यात्रियों से फीडबैक के आधार पर ए1 और ए श्रेणी के स्टेशनों का रैंक निर्धारण करना; वेस्ट सेग्रीगेशन और रिसाइक्लिंग सेंटर; 'जागरूकता अभियान'; 30,000 अतिरिक्त जैव-शौचालय; वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और महिला यात्रियों के लिए चुनिंदा स्टेशनों के सभी प्लेटफार्मों पर पोर्टेबल जैव-शौचालय मुहैया कराना, शौचालय बनाने और उनके रखरखाव के लिए विज्ञापन अधिकार, सीएसआर, सामाजिक संगठनों की ओर से स्वैच्छिक सहायता।

स्टेशनों पर खानपान और स्टॉल- चरणबद्ध आधार पर आईआरसीटीसी को खानपान सेवाओं का प्रबंध; खानपान सेवाओं को वैकल्पिक बनाने की संभावना का पता लगाना, आईआरसीटीसी द्वारा परिचालित 10 अन्य बेस किचन की व्यवस्था; स्थानीय स्वामित्व और सशक्तिकरण के लिए, जिला निवासियों को स्टेशनों पर वाणिज्यिक लाइसेंस देने में प्राथमिकता।

ठहराव: यात्रियों की सुविधा के लिए सभी परिचालनिक हॉल्ट स्टेशनों को वाणिज्यिक हॉल्ट में बदलना।

रेल मित्र सेवा: स्टेशनों पर वृद्धों और दिव्यांग यात्रियों की सहायता के लिए कोंकण रेलवे में सारथी सेवा का विस्तार, मौजूदा सेवाओं को सुदृढ़ करने, जिसमें यात्री, मौजूदा पिक अप एंड ड्राप सेवा और व्हील चेयर सेवाओं के अलावा भुगतान आधार पर बैटरी चालित कारें, कुली सेवाएं आदि बुक कर सकते हैं।

दिव्यांगों के लिए उपाय - पुन: विकसित किए जा रहे सभी स्टेशनों का दिव्यांगों द्वारा इस्तेमाल किया जा सके; आगामी वित्त वर्ष के दौरान हम ए1 श्रेणी स्टेशन के प्रत्येक प्लेटफार्म पर दिव्यांगों के लिए कम-से-कम एक शौचालय उपलब्ध करवाना और इन स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में व्हील चेअरों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करना।

यात्रियों के लिए यात्रा बीमा- रेल यात्राओं की बुकिंग के समय वैकल्पिक यात्रा बीमा उपलब्ध कराना।

विश्रामालयों की घंटे के आधार पर बुकिंग- आईआरसीटीसी को सौंपा जाएगा।

जननी सेवा: गाड़ियों में बच्चों के लिए खानपान के पदार्थ, शिशु आहार, गरम दूध और गर्म पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

स्मार्ट (स्पेशली मोडिफाइड एस्थैटिक रिफ्रेशिंग ट्रैवल) सवारी डिब्बे-वहन क्षमता को बढ़ाने और आटोमेटिक दरवाजे, बार-कोड रीडर, बायो वैक्यूम टॉयलेट, वॉटर लेवल इंडिकेटर, पंदुच के भीतर कूड़ेदान की व्यवस्था, एर्गोनोमिक सीटें, बेहतर साज-सज्जा, वेंडिंग मशीनें, मनोरंजन स्क्रीन, विज्ञापन के लिए एलईडी लिट बोर्ड, पी ए सिस्टम सुनिश्चित करने के लिए सवारी डिब्बों के डिजाइन और लेआउट।

मोबाइल ऐप -टिकट संबंधी सभी कार्य करने और शिकायतों के निवारण करने और सुझाव प्राप्त करने के लिए दो मोबाइल ऐप में सभी सुविधाएं एकीकृत करना।

ग्राहक इंटर फेस में सुधार लाना -ग्राहकों से सीधे संपर्क में आने वाले रेल कर्मचारियों तथा उन कर्मचारियों, जिन्हें हम सेवा प्रदाताओं के जरिए नियुक्त करते हैं, को कार्य-कुशल बनाना, गाड़ियों में सूचना बोर्ड लगाएंगे जिनमें गाड़ियों में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं का उल्लेख होगा और यात्रियों को आने वाले स्टेशनों के बारे में रियल टाइम सूचना प्रदान करने के लिए सवारी डिब्बों के भीतर जीपीएस आधारित डिजिटल डिस्पले बोर्ड भी लागए जाएंगे। 2000 स्टेशनों पर रेल डिस्पले नेटवर्क नामक 20,000 स्क्रीन वाले एक हाई-टेक केन्द्रीकृत नेटवर्क स्थापित करने का कार्य जारी है। इससे यात्रियों को रियल टाइम सूचना उपलब्ध कराई जा सकेगी और बड़े पैमाने पर

विज्ञापन की पर्याप्त संभावनाएं भी बढ़ेंगी। ए1 श्रेणी के सभी स्टेशनों पर यथोचित शक्तिसंपन्न स्टेशन निदेशक तैनात किए जाएंगे जिनकी सहायता के लिए विभिन्न कोटि के कर्मचारियों का एक कार्यदल भी होगा; गाड़ी में इन सभी सुविधाओं के लिए एक व्यक्ति को जवाबदेह बनाया जाएगा।

- धार्मिक महत्व के केन्द्रों पर यात्रियों की सुविधाओं की व्यवस्था और स्टेशनों के सौंदर्यीकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू करना इनमें अजमेर, अमृतसर, बिहार शरीफ, चेंगनूर, द्वारका, गया, हरिद्वार, मथुरा, नागपट्टनम, नांदेड़, नासिक, पाली, पारसनाथ, पुरी, तिरूपति, वेलंकन्नी, वाराणसी और वास्को शामिल हैं; इसके अलावा, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए आस्था सर्किट गाड़ियां चलाने की भी मंशा है।
- पोर्टर- हमारे सहायक उन्हें नई वर्दी देने और सॉफ्ट स्किल में उन्हें प्रशिक्षित करने की हमारी मंशा है, अब से, उन्हें सहायक के नाम से पुकारा जाएगा।
- हाई स्पीड रेल- जापान सरकार की सहायता से अहमदाबाद से मुम्बई तक एक हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर का कार्य किया जा रहा है। हाई स्पीड परियोजनाएं निष्पादित करने के लिए एक विशेष प्रयोजन योजना इस माह में पंजीकृत की जाएगी। इस परियोजना का मुख्य लाभ भारतीय रेल को उन्नत प्रौद्योगिकी और नवीन विनिर्माण क्षमता मुहैया कराना होगा।
- मनोरंजन- गाडियों में मनोरंजन की व्यवस्था करने के लिए एफएम रेडियो स्टेशनों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव; सभी आरक्षित श्रेणियों के यात्रियों को **'रेल बंधु'** सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना।

यात्री यातायात – उपनगरीय यातायात : एमयूटीपी–III के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त। चर्चगेट–विरार और सीएसटीएम-पनवेल खंडों के बीच ऐलीवेटिड उपनगरीय कॉरिडोरों के लिए शीघ्र निविदा देना; दिल्ली में रिंग रेलवे प्रणाली को पुन: चालू कराना; अहमदाबाद, बेंगलुरू, हैदराबाद, चैन्ने और तिरूवनंतपुरम में विकास की योजना राज्य सरकारों के साथ भागीदारी करके उपनगरीय प्रणाली के विस्तार के लिए नए निवेश ढांचा तैयार करना।

परिवहन में भारतीय रेल के हिस्से को पुन: प्राप्त करना

भारतीय रेल पर फ्रेट बास्केट का विस्तार- पायलट आधार पर समय-सारणीबद्ध फ्रेट–कंटेनर, पार्सल और विशेष पण्यों के लिए गाड़ियां चलाना, कोयला और विनिर्दिष्ट खनिज अयस्कों को छोड़कर प्रत्येक किस्म के यातायात के लिए कंटेनर सेक्टर खोलना, गैर-व्यस्त अवधि के दौरान आंशिक रूप से भरी हुए गाड़ियां चलाने की अनुमति। सभी मौजूदा टर्मिनलों/शेडों, जहां-कहीं व्यावहारिक पाया जाए, को कंटेनर यातायात की अनुमति प्रदान करना।

टैरिफ को युक्तिसंगत बनाना यातायात के अन्य साधनों की तुलना में एक प्रतिस्पर्धी भाड़ा संरचना तैयार करने, मल्टी-पाइंट लदान/उतराई और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग बढ़ाने के लिए भिन्न-भिन्न भाड़ा दरें। लागू करने के लिए टैरिफ नीति की समीक्षा। पूर्व निर्धारित कीमत वृद्धि सिद्धांतों का इस्तेमाल करके महत्वपूर्ण माल यातायात ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक टैरिफ करारों पर हस्ताक्षर।

टर्मिनल क्षमता का निर्माण पीपीपी माध्यम से रेल साइड लॉजिस्टिक पार्कों और वेयरहाउसों को विकसित करने का प्रस्ताव, **ट्रांसलोक** द्वारा कम से कम 10 माल शेड विकसित किए जाएंगे, 2016-17 में ट्रांसलोक लॉजिस्टिक कंपनी। शीघ्र ही चेन्नै में भारत के पहले रेल ऑटो हब का उद्घाटन। माल यातायात टर्मिनलों के निकट खाली भूमि पर कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं के विकास को बढ़ावा। स्थानीय किसानों और मछुआरों को इस सुविधा का इस्तेमाल करने में प्राथमिकता दी जाएगी। अगले 3 माह में इस संबंध में एक नीति जारी की जाएगी।

किराए से इतर राजस्व

- स्टेशन पुनर्विकास; रेलपथ के आस-पास की भूमि का मौद्रीकरण; सॉफ्ट परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण- वेबसाइट, डाटा, आदि; विज्ञापन- 2016-17 में 2015-16 के राजस्व को 4 गुना करने का लक्ष्य; पार्सल व्यवसाय को ओवरहॉल करना- इस सेक्टर को कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों के लिए खोलने सहित मौजूदा पार्सल नीतियों को उदार

बनाना; विनिर्माण कार्यकलापों से राजस्व- 2020 तक लगभग 4,000 करोड़ रुपए तक वार्षिक राजस्व जुटाने का लक्ष्य।

प्रक्रिया में सुधार

- **ईपीसी परियोजना** मानक दस्तावेजों को अंतिम रूप दे दिया है, 2016-17 में इसके जरिए कम से कम 20 परियोजनाएं कार्यान्वित करेंगे; 2017-18 में 300 करोड़ रु. से अधिक की लागत वाले सभी निर्माण कार्यों को ईपीसी ठेकों के जरिए प्रदान करने का प्रयास।
- **कार्य निष्पादन आऊटपुट पैरामीटर आधारित ठेका-** ठेकों की सेवाओं को एकीकृत करने के लिए उनकी समीक्षा करना उन्हें आसान बनाना तथा इनके परिणाम पर ध्यान देना।
- **परियोजना प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग-** बड़ी परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति की कहीं से भी समीक्षा करने के लिए नवीनतम ड्रोन और जियो स्पैटियल आधारित सैटलाइट प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की मंशा; 2016-17 में इस मोड के जरिए समर्पित माल यातायात गलियारे की प्रगति की निगरानी करना।
- **समूची प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का एकीकरण-** हमने समूची प्रणाली का एकीकरण शुरू किया है जो क्षैतिज और लंबवत दोनों प्रकार से नवरचना में भागीदारी के मॉडल के माध्यम से चलाए जाने वाले उद्यम संसाधन प्रणाली के समान है।

रेल विकास प्राधिकरण

- सेवाओं की उचित कीमत निर्धारण, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, ग्राहकों के हितों का संरक्षण, कार्यकुशलता के मानकों के निर्धारण; हितधारियों से विस्तृत परामर्श के पश्चात् ड्राफ्ट बिल तैयार करना।

नवारंभ- एक नई शुरूआत

- नवीनीकरण- संरचनागत बदलाव
  संगठनात्मक पुनर्संरचना- रेलवे बोर्ड का व्यावसायिक तरीके से पुनर्गठन करने और इस संगठन का कुशलतापूर्वक नेतृत्व करने के लिए अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड को समुचित शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव। शुरुआत में किराए से इतर राजस्व, गति बढ़ाने, चालन शक्ति और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए रेलवे बोर्ड के भीतर क्रॉस फंक्शनल निदेशालयों की स्थापना की जानी है; अधिकारियों की नई भर्ती के लिए हम संवर्गों के एकीकरण की संभावना का पता लगाएंगे; भारतीय रेल के साथ कारोबार को सफल बनाने के लिए पीपीपी सेल को सृदृढ़ करना।
- सशक्तिकरण-हमारी योजना पद्धतियों में सुधार करना।
  मध्यावधि (5 वर्ष) तथा दीर्घावधि (10 वर्ष) कोरपोरेट योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए रेलवे योजना एवं निवेश संगठन की स्थापना करना; उन परियोजनाओं की पहचान करना है जो कोरपोरेट लक्ष्यों को पूरा करें। रेलनेटवर्क और परिवहन के अन्य साधनों में सामंजस्य स्थापित करने और उन्हें एकीकृत करने तथा देशभर में निर्बाध बहुआयामी परिवहन नेटवर्क का लक्ष्य हासिल करने के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करने का वातावरण बनाने के लिए राष्ट्रीय रेल योजना।
- एकीकरण- कांसोलिडेशन: भारतीय रेलवे के स्वामित्व वाली कंपनियों की होल्डिंग कंपनी बनाना।
- शोध और विकास – भविष्य के लिए निवेश: एक शोध और विकास संगठन, स्पेशल रेलवे इस्टेब्लिसमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट (श्रेष्ठ) का गठन करना, अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन (अ.अ.मा.सं.) केवल दिन-प्रतिदिन के मामलों पर ही ध्यान केन्द्रित करेगा, जबकि श्रेष्ठ दीर्घकालिक शोध करेगा।
- डाटा विश्लेषण: एक डेडीकेटेड क्रॉस फंक्शनल टीम, जिसे स्पेशल यूनिट फॉर ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एण्ड एनॉलिटिक्स (सूत्र) कहा जाएगा, का गठन किया जाएगा जो विस्तृत विश्लेषण करेगी ताकि अधिकतम निवेश और प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लिए जा सकें।
- नवरचना-इनोवेशन: नवरचना में सहायता प्रदान करने के लिए कर्मचारियों, स्टार्टअप्स तथा प्रगतिपरक छोटे व्यापारियों के लिए 50 करोड़ रुपए अलग से रख रहे हैं।

अवतरण- भारतीय रेल के ट्रांसफॉरमेशन के लिए सात मिशन

- प्रत्येक मिशन का प्रधान, एक मिशन निदेशक होगा जो अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड को सीधे रिपोर्ट करेगा। वह एक ऐसे क्रॉस फंक्शनल टीम का प्रधान होगा, जिसे लक्ष्य के अनुसार समय पर कार्य पूरा किया जाना सुनिश्चित

करने के लिए सभी संगत निर्णय लेने का अधिकार होगा। इस मिशन के लिए वार्षिक परिणाम के आधार पर कार्य-निष्पादन के लक्ष्य घोषित किए जाएंगे और अल्पकालिक, मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक कार्यान्वयन योजनाओं को अंतिम रूप देंगे और तदनुसार कार्रवाई करेंगे।

- 25 टन धुरा-भार के लिए मिशन 25 टन, संरक्षा के लिए मिशन जीरो दुर्घटना, मिशन पीएसीई (खरीद और खपत में कुशलता), उच्च गति के लिए मिशन रफ्तार, मिशन 2016-17 में 100 साइडिंगों/माल यातायात टर्मिनलों को चालू करने के लिए मिशन शतक, लेखांकन में पद्धतियों में सुधार के लिए मिशन बुक कीपिंग से आगे, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के चालू होने के बाद इस भारी नई क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए ब्लू-प्रिंट तैयार करने हेतु मिशन क्षमता उपयोग।

सामाजिक पहल और सहारा कार्य: मानव संसाधन/कौशल, समाजिक पहल, पर्यावरण

- रेलवे अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों के बीच आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के लिए हम स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समझौता करना; 5 रेलवे अस्पतालों में 'आयुष' प्रणाली शुरू करना; गैंगमैनों को आने वाली गाड़ियों के बारे में सूचित करने के लिए एक उपकरण दिया जाएगा जिसे 'रक्षक' कहा जाएगा, पेट्रोलिंग के समय ढोए जाने वाले औजारों का भार कम करना। हमारे लोको पायलटों के लिए कैब में प्रसाधन एवं वातानुकूलन की भी व्यवस्था करना।
- दो पीठों की स्थापना- एक महत्वपूर्ण वित्त, अनुसंधान एवं नीति विकास से संबंधित सी टी वेणुगोपाल पीठ और दूसरी भारतीय रेलवे के लिए जियो स्पेटल प्रौद्योगिकी से संबंधित कल्पना चावला पीठ।
- प्रत्येक वर्ष इंजीनियरी एवं एमबीए स्कूलों के 100 छात्रों को 2-6 महीनें की इंटर्नशिप देंगे।
- कौशल विकास मंत्रालय के साथ भागीदारी - भारतीय रेल परिसरों में विशाल कौशल विकास।
- गैर-कर्षण क्षेत्र में ऊर्जा खपत 10% से 15% तक कम करने के लिए ऊर्जा ऑडिट करना। बिजली की नई व्यवस्था में केवल एलईडी लाइट की ही व्यवस्था करना और सभी रेलवे स्टेशनों पर आगामी 2 से 3 वर्षों में एलईडी लाइटें लगा दी जाएंगी।
- पर्यावरणीय मान्यता, जल प्रबंधन और कूड़े-कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कार्य योजना तैयार करना। 2000 से अधिक स्थानों पर वर्षा जल संग्रहण (आरडब्ल्यूएच) की सुविधा मुहैया करना। स्टील के पुलों पर स्टील के स्लीपरों के स्थान पर रिसाईक्लिंग प्लास्टिक वेस्ट से तैयार पर्यावरण हितैषी कम्पोजिट स्लीपरों का सभी गर्डर पुलों में इस्तेमाल किया जाएगा।
- आगामी वर्षों में वाटर रिसाइक्लिंग प्लांट लगाने के लिए 32 स्टेशनों और 10 कोचिंग डिपुओं की पहचान की गई है।

पर्यटन

- पर्यटक सर्किट गाड़ियां चलाने के लिए राज्य सरकारों के साथ भागीदारी करना; हाल ही में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय को अपग्रेड किया गया है। रेलवे संग्रहालयों और यूनेस्को विश्व धरोहर रेलों के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देना।
- अपने राष्ट्रीय पशु, बाघ के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक संपूर्ण पैकेज शुरू करना जिसमें गाड़ी यात्रा, सफारी एवं आवास शामिल होगा। इसमें कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ वन्यजीव सर्किट शामिल किया जाएगा।

भाषण के अनुलग्नक 1 में भारतीय रेलों के वित्तीय निष्पादन और प्राप्तियों एवं व्यय के अनुमान का ब्यौरा दिया गया है।

वित्तीय निष्पादन 2015-16

- सकल यातायात प्राप्तियों में 1,83,578 करोड़ रु. के बजट अनुमान लक्ष्य की तुलना में संशोधित अनुमान 2015-16 में 15,744 करोड़ रु. की शुद्ध कमी। वर्ष 2013-14 से उपनगरीय और अनुपनगरीय दोनों यात्रा के गैर-पीआरएस सेगमेंट में लगातार नकारात्मक वृद्धि के रूख को ध्यान में रखते हुए यात्री आमदनी कम हुई।
- कोर सेक्टर से कम मांग के कारण इस फ्रेट आमदनी में वृद्धि प्रभावित हुई जिसके परिणामस्वरूप संशोधित अनुमान 2015-16 में इस लक्ष्य को 1,11,853 करोड़ रु. पर पुनः निर्धारित करना पड़ा।
- साधारण संचालन व्यय (ओडब्ल्यूई) पर नियंत्रण रखने के लिए कड़े आर्थिक और किफ़ायती उपाय अपनाए गए, जिनके कारण 1,19,410 करोड़ रु. के बजट में निर्धारित साधारण संचालन व्यय वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमान में घटकर 1,10,690 करोड़ रु. हो गया अर्थात् इसमें 8,720 करोड़ रु. की गिरावट आई।
- बजट अनुमान से पेंशन निधि में 34,900 करोड़ रु. का विनियोजन हुआ। बहरहाल, इस रूख के आधार पर, संशोधित अनुमान में पेंशन भुगतान में 34,500 करोड़ रु. की मामूली सी कमी हुई है।
- आंतरिक संसाधन सृजन में कमी आई और 7,900 करोड़ रु. की व्यवस्था करके 2015-16 के बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान में मूल्यह्रास आरक्षित निधि में 5,500 करोड़ रु. की कमी की गई है। वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमान में व्यय की तुलना में आमदनी का आधिक्य 11,402.40 करोड़ रु. है
- वर्ष 2015-16 के लिए योजना आकार अर्थात् बजट अनुमान स्तर पर 1,00,000 करोड़ रु. आंका गया है।

बजट अनुमान 2016-17:

- राजस्व में वृद्धि और उपयुक्त निवेश सुनिश्चित करने की मंशा है जिससे 2015-16 में शुरू किए गए भीड़भाड़ कम करने और लाइन क्षमता बढ़ाने संबंधी कार्यों को जारी रखा जा सकेगा। परियोजनाओं को सुनिश्चित धनराशि मुहैया कराने के लिए बढ़े हुए पूंजी व्यय पर बल दिया गया है, जिसमें वित्त व्यवस्था के विभिन्न स्रोतों का मिश्रण है।
- सकल यातायात प्राप्तियां 1,84,820 करोड़ रु. रखी गई हैं। यात्री यातायात से आमदनियां 12.4% पर निर्धारित की गई है और तदनुसार आमदनी संबंधी लक्ष्य 51,012 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं। अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र में लाभप्रद वृद्धि की प्रत्याशा में माल यातायात 50 मिलियन टन के वर्धमान यातायात पर निर्धारित किया गया है। तदनुसार, माल यातायात से आमदनी 1,17,933 करोड़ रु. प्रस्तावित की गई है। अन्य कोचिंग एवं विविध आमदनियां क्रमशः 6,185 करोड़ रु. और 9,590.3 करोड़ रु. निर्धारित की गई है।
- साधारण संचालन व्यय के अंतर्गत, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रावधान किया गया है।
- वर्ष 2016-17 में पेंशन निकासी 45,500 करोड़ रु. निर्धारित की गई है।
- उच्चतर कर्मचारी लागत और पेंशन दायिता से रेलों की आंतरिक संसाधन स्थिति प्रभावित होती है। तदनुसार राजस्व से मू.आ.नि. को विनियोजन 3,200 करोड़ रु. और उत्पादन इकाइयों से 200 करोड़ रु. रखा गया है। सकल खर्च के जरिए शुद्ध आधार पर मू.आ.नि से 3,160 करोड़ रु. की निकासी का प्रस्ताव है, यद्यपि वार्षिक योजना, जिसके लिए 7,160 करोड़ रु. का अनुमान लगाया गया है, में मू.आ.नि को सकल खर्च से पूरा किया जाएगा। पूंजी निधि को 5,750 करोड़ रु. विनियोजित करने का प्रस्ताव है। इस निधि में पूर्ववर्ती शेष से 1,250 करोड़ रु. निकाल कर आईआरएफसी को पट्टा प्रभारों के मूल घटक के भुगतान के लिए 7,000 करोड़ रु. की पूर्ति की जाएगी।
- वर्ष 2016-17 में रेलवे 1,21,000 करोड़ रु. का योजना आकार तैयार कर रही है।

भाषण के अनुलग्नक-2 में 2015-16 में की गई बजट उद्घोषणाओं के कार्यान्वयन का ब्यौरा दिया गया है।

*****